प्रेस विज्ञप्ति / Press Release **19 दिसंबर / December, 2020**

असम में एमएसएमई पारितंत्र के विकास हेतु सिडबी द्वारा असम सरकार के साथ गठबंधन

SIDBI joins hands with Government of Assam for the Development of MSME Ecosystem in the State

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न राष्ट्र की शीर्ष संस्था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने असम सरकार के साथ राज्य में एमएसएमई पारितंत्र को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान श्री चंद्र मोहन पटोवारी, असम सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री, वाणिज्य और उद्योग विभाग, परिवहन, संसदीय कार्य, एक्ट ईस्ट नीति मामले, कौशल, रोजगार और उद्यमिता विकास, की उपस्थिति में श्री डॉ. पाबित्रा राम खौण्ड, सचिव, असम सरकार और श्री डॉ आर के सिंह, महाप्रबंधक, सिडबी द्वारा किया गया।

Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the country's principal financial institution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), has entered a Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of Assam (GoA) to develop the MSME ecosystem in the State. The MoU was exchanged by Shri Dr. Pabitra Ram Khaund, Secretary to the Government of Assam and Dr. R. K. Singh, General Manager, SIDBI in the presence of Shri. Chandra Mohan Patowary, Hon'ble Cabinet Minister for Department of Commerce & Industry, Transport, Parliamentary Affairs, Act East Policy Affairs, Skill, Employment & Entrepreneurship Development, Govt of Assam.

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सिडबी द्वारा असम सरकार के साथ मिलकर एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की नियुक्ति की जाएगी। पीएमयू राज्य में एमएसएमई की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करने में असम सरकार का समर्थन करेगा। पीएमयू की व्यापक रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं:

Under the MoU, a Project Management Unit (PMU) will be deployed by SIDBI with GoA. The PMU will support the GoA in making necessary interventions for enhancing efficacy of MSMEs in the state. PMU' few broad contours includes the following:

क) इक्विटी समर्थन, ब्याज अनुदान, दबावग्रस्त एमएसएमई के निराकरण के क्षेत्रों में योजना की रूपरेखा तैयार करना,

a) Designing of scheme(s) in the areas of equity support, interest subvention, resolution of stressed MSMEs,

ख) राज्य में एमएसएमई की ओर लक्षित / लाभार्थ उपलब्ध योजनाओं / अंतरवर्तनों / पहल / परियोजनाओं, आदि की मौजूदा रूपरेखा का अध्ययन और प्रभावकारिता बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से आशोधन करने हेतु सुझाव देना,

b) Study of the existing framework of schemes / interventions / initiatives / projects, etc. available for benefit of / targeted towards MSMEs in the state and suggesting modifications with the objective of enhancing efficacy and removal of bottlenecks,

ग) राज्य में एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे जीईएमएस आदि में सम्मिलित करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करना।

c) Preparation of a process for handholding MSME in the state for their onboarding into digital platforms such as PSB Loans In 59Minutes, Stock Exchange listing, e-commerce platforms such as GEMs, etc.

घ) आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत असम सरकार द्वारा एमएसएमई इकाईयों के लिए गतिविधियों / योजनाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाना

d) Facilitating awareness on activities / schemes for MSMEs by GoA under Atmanirbhar Bharat Abhiyan

इस अवसर पर माननीय मंत्री ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन असम राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। असम राज्य सक्रिय रूप से इस क्षेत्र को रोजगार और विकास के एक समाधान के रूप में चिह्नित कर रहा है। इस अवसर पर, डॉ. के के द्विवेदी, आईएएस, असम सरकार के कमिश्नर और सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन असंगठित क्षेत्र को आकर्षित करने में मदद करेगा ताकि वे और अधिक संगठित हो कर उभर सकें और इस पारितंत्र में उपलब्ध लाभों को ग्रहण कर सकें। सिडबी के महाप्रबंधक डॉ. आर के सिंह ने कहा, "हम 11 राज्यों में एमएसएमई पारितंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन 9 वां समझौता ज्ञापन है। सिडबी स्टेट नोडल यूनिट के साथ एक विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त करेगी। इस व्यवस्था के समानांतर रूप में, सिडबी ने प्रवासियों सहित समाज के निचले तबकों में आय सृजन गतिविधियों के लिए एसआरएलएम, असम के साथ भी सहयोग शुरू किया है। इस अवसर पर,

असम वित्तीय निगम के अध्यक्ष श्री विजय कुमार गुप्ता, श्री मनोज लुंडिया, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, के साथ सुश्री कृष्णा बरुआ, मिशन निदेशक, असम ग्रामीण आजीविका मिशन भी उपस्थित थीं ।

On this occasion, the Hon'ble Minister stated that this MoU would be beneficial to the Micro and small enterprises in the State of Assam. State of Assam is proactively looking this sector as a solution for employment and growth. On this occasion, Dr. K K. Dwivedi, I.A.S., Commissioner and Secretary to the GoA, Industries and Commerce Department said that this MoU shall help in attracting the un-organised sector to emerge more organized and avail benefits available in the Eco System. Dr. R. K. Singh, General Manager of SIDBI said, "We are working towards strengthening the MSME Eco System in the 11 States and MoU with Government of Assam is the 9th MoU. SIDBI would place an expert agency with the State Nodal Unit. Parallel to this arrangement, SIDBI has also initiated collaboration with SRLM, Assam to serve income generating activities at base of the pyramid including migrants. On this Shri Vijay Kumar Gupta, Chairman, Assam Financial Corporation, Shri Manoj Lundia, President, Laghu Udhyog Bharati, Ms. Krishna Baruah, Mission Director, Assam Rural Livelihood Mission were also present.

सिडबी के बारे में : 1990 में अपने गठन के बाद से, सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। चाहे वे पारंपरिक, छोटे घरेलू उद्यमी हों, पिरामिड के सबसे निचले स्तर के उद्यमी हों, या फिर उच्च-स्तरीय ज्ञान आधारित उद्यमी हों, सिडबी ने अपने विभिन्न ऋणों तथा विकास कार्यों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के जीवन को प्रभावित किया है।

अधिक जानने के लिए, देखें : https://www.sidbi.in

About SIDBI: Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements.

To know more, check out: https://www.sidbi.in